परियोजना	क्रांतिकता प्राप्त करने संबंधी कार्यक्रम		लागत अनुमान	
	मूल	वास्तविक। प्रत्याशित	मूल	प्रत्याशित (करोड़ रुपए)
ककरापार-1 तथा 2	दिसम्बर, 90 दिसम्बर 91	सितम्बर 92 दिसम्बर 94	382.50	1025+ (आई डी सी) 310
	(मूल संस्वीकृति जुलाई, 1981 में प्राप्त हुई)			
कैगा-1 तथा 2	जून, 95 दिसम्बर, 95	जून, 96 दिसम्बर, 96	730.72	1590+ (आई डी सी) 685
	(मूल संस्वीकृति जून, 1987 में प्राप्त हुई)			
राजस्थान-3 तथा 4	मई, 95 नवम्बर, 95	नवम्बर, 96 मई, 97	711.57	1450+ (आई डी सी) 657
	(मूल संस्वीकृति नवम्बर, 1986 में प्राप्त हुई)			

इन परियोजनाओं के लागत अनुमानों में सामान्य रूप से जो वृद्धि हुई है वह निर्माण के दौरान लगने वाले ब्याज को शामिल करने के अलावा परियोजना के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने, मूल्यों में वृद्धि होने, विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में विभिन्नता होने, रूपए का अवमूल्यन होने, करों और शुल्कों आदि में परिवर्तन होने की वजह से भी हुई है।

ककरापार-1 में विलम्ब नरोरा के भूकम्पनीय डिजायन के अनुरूप ककरापार परियोजना के डिजायन में संशोधन करने, थ्री माइल आइलैंड (टी एम आई) के अनुभव के आधार पर की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने, यूनिट में आग लगने की स्थानीय घटना होने, पाइपिंग हार्डवेयर की आपूर्ति में देरी होने, पाइपों को लगाने के लिए ठेका देने, यंत्रीकरण और नियंत्रण मदों की आपूर्ति में विलम्ब होने की वजह से हुआ था। ककरापार-2 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यूनिट-1 के पूरा होने के 1 वर्ष के बाद पूरा किया जाना था। इसके अतिरिक्त, ककरापार-2 को चालू करने में हुई देरी का कारण यह था कि इससे पहले के यूनिटों को परिचालित करने से प्राप्त अनुभव के आधार पर सुरक्षा संबंधी आवश्यक अभियांत्रिकी परिवर्तन करने पड़े जिनके परिणामस्वरूप कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई और यह काम और जटिल हो गया। कैगा 1 तथा 2 और राजस्थान 3 तथा 4 के मामले में निर्धारित से अधिक समय लगने का कारण सुरक्षा संबंधी नई अपेक्षाओं से उत्पन्न सिविल इंजीनियरी डिजायन की विस्तृत रूप से पुनरीक्षा करने की जरूरत की वजह से सिविल कार्यों में प्रारम्भिक रूप से विलम्ब होना था। राजस्थान परवाणु विद्युत परियोजना 3 तथा 4 के मामले में मुख्य संयंत्र के लिए सिविल कार्यों को करने के वास्ते ठेकेदार के लिए निर्धारित की गई धनराशी को प्राप्त करने में पेश आने वाली कठिनाई एक अतिरिक्त कारक था।

मध्य प्रदेश में यूरेनियम की खोज

2588. **श्री शिव प्रसाद धनपुरिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मंडला और बालाघाट के सीधे क्षेत्र के 30 वर्ग किलोमीटर में यूरेनियम के भंडार की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त यूरेनियम कहां परिष्कृत किया जा रहा है और यहां से कितना यूरेनियम प्राप्त किया गया तथा कितना परिष्कृत किया गया; और

(ग) क्या सरकार का बाह्य आक्रमण से सुरक्षित मध्य प्रदेश में किसी स्थल पर परिष्कृत यूरेनियम के संचय हेतु एक केन्द्र को स्थापित करने का विचार है?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग

के परवाणु खनिज प्रभाग ने परवाणु खनिजों के लिए नियमित सर्वेक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के अनेक क्षेत्रों में यूरेनियम के लिए पूर्वेक्षण किया है । अभी तक उस क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विकिरणसक्रिया खनिजों के किसी भी निक्षेप के होने का पता नहीं लगा है ।

(ख) और (ग) यदि इस क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य कोई निक्षेप पाया गया तो, यूरेनियम अयस्क का खनन करने और उसका पेषण करने के वास्ते एक परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ।

Implementation of Nuclear Power Project affected by Paucity of Funds

2489. SHRI VIREN J. SHAH : Will the Prime Minister be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 263 given in the Rajya Sabha on 8th December 1994 and State :

(a) how far the paucity of funds has affected the implementation of the different nuclear power projects and resulted in slowing down of the nuclear programme; and

(b) what steps Government have taken or propose to take to provide adequate and timely funds for these plants so that these plants are completed in time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : (a) Of the nuclear power projects originally included in the Eighth Five Year Plan, commencement of work on Tarapur 3 & 4 (2×500 MWe) Rajasthan 5 & 6 (2 × 500 MWe) and Kaiga, 3 to 6 (4×220 MWe) has been affected due to constraints of funds, though advance action for procurement of equipment with long delivery period has been taken.

(b) Efforts are on for making available additional resources from the Government within the overall resource availability, achieving better performance of the existing Power Stations and vigorous action for realising of outstandings from the State Electricity Boards and also exploring the possibilities of setting up of some of the Planned Schemes as Joint Sector Projects with the concerned State Governments.

Mishaps in Nuclear Installations

2490. SHRI B. K. HARIPRASAD : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there have been several mishaps in our Nuclear Reactors and power plants etc. and if so, the details thereof for the nuclear installations since inception; including any other ancillary sterilization and irradiation plants ;

(b) whether in view of the new open pragmatic policies of the Government if such mishaps are made public speedily in order to get feed-back for improvements from the public and also make them alert from any dangers and promote accountability of the staff who prefer to hide such information ;and

(c) weether in view of the problems created by disposal of the spent fuel and other material and exorbitant costs and dangers incolved, Government would review its policies on nuclear power etc.

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : (a) The events in nuclear power plants have been classified by the International Nuclear Event Scale System of the International Atomic Energy Agency in a scale ranging from 0 to 7 in increasing order of severity. Events rated upto and including Level-3 are classified as incidents and the incidents rated above scale-3 are termed accidents.

No nuclear accidents have so far taken place in any nuclear power plant in India. There have been no mishaps in the ancilliary sterilisation and radiation plants involving occupational workers/public.

(b) On nuclear safety the Government has been pursuing a transparent policy. Government has responded promptly and taken appropriate measures whenever any incident has occurred in any nuclear installation. In case of incidents in nuclear installations, the information which merits public attention has always been made available and there is no attempt to withhold information from the public.

(c) The Indian nuclear energy programme does not visualise the disposal of spent nuclear fuel as a waste. But it is being reprocessed to recover the fissile materials for reuse as fuel. Hence, the question of reviewing the policy with respect to nuclear power does not arise.